

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2017—आश्विन 25, शक 1939

#### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

अधि. क्र. 82-एफ 1-42-2017-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 37 तथा 73 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 70 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 5 के उप-नियम (5) के खण्ड (ग्यारह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(बारह) उपरोक्त उपनियमों में दिए गए निविदा संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त राज्य सरकार, नगरीय निकायों को, केन्द्र सरकार अथवा मध्यप्रदेश सरकार के किसी उपक्रम/संस्था/पोर्टल से किसी कार्य को कराए जाने अथवा सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी.”

Not. No. 82-F 1-42-2017-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 37 and 73 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipalities (the Conduct of Business of the Mayor-in-Council / President-in-Council and the powers and functions of the Authorities) Rules, 1998, namely :—

#### AMENDMENT

1. In the said rules in rule 5, in sub-rule (5), after clause (xi), the following clause shall be added, namely :—

“(xii) In addition to the provisions related to the tender prescribed in above sub-rules, the State Government may authorize the Urban Local Body to execute any work or purchase material from any enterprise / organization / portal of Union Government or State Government.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, उपसचिव.